आई.सी.एम.आर., मध्यप्रदेश सरकार और एफडीईसी–इंडिया ने मंडला, मध्यप्रदेश में मलेरिया मुक्त भारत डिमांस्ट्रेशन परियोजना प्रारंभ करने के लिए त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए

परियोजना जनवरी, 2017 से मंडला में 1233 ग्रामों में प्रारंभ होने वाली है

- सन फार्मा ने मंडला मलेरिया विलोपन डिमांस्ट्रेशन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एफडीईसी–इंडिया की स्थापना की है
- यह करार अन्य सरकारी या प्राइवेट स्टेकहोल्डर्स को एफडीईसी–इंडिया के साथ साझेदारी में मंडला परियोजना या इसी प्रकार की परियोजना में शामिल होने की अनुमति देता है
- मंडला परियोजना से सीखे गए सबक मध्यप्रदेश एवं भारत के बाकी हिस्सों में मलेरिया के विलोपन के लिए उपयोगी होंगे

मंडला/नई दिल्ली/मुंबई, 15 नवंबर, 2016 – सन फार्मा

(Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE:SUNPHARMA, BSE:524715, '' सन फार्मा'' अपनी सहायक और एसोसिएट कंपनियों सहित) ने आज आई.सी.एम.आर., मध्यप्रदेश सरकार और 'फाउंडेशन फॉर डिजीस एलीमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया' (एफडीईसी–इंडिया) के बीच मध्यप्रदेश के मंडला में मलेरिया मुक्त भारत डिमांस्ट्रेशन परियोजना प्रारंभ करने के लिए त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा की है। सन फार्मा द्वारा अपने सी.एस.आर. कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में रोग विलोपन एवं नियंत्रण के संबंध में उठाए जा रहे कदमों के लिए 'फाउंडेशन फॉर डिजीस एलीमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया' (एफडीईसी–इंडिया) की स्थापना की गई है। मलेरिया मुक्त भारत संबंधी पहल की घोषणा अप्रैल, 2016 में आईसीएमआर एवं सन फार्मा के बीच अपेक्षाकृत व्यापक समझौता–पत्र (MOU) के हिस्से के तौर पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ट्रांसलेशनल हैल्थ साइंसेज का विकास एवं रोग नियंत्रण एवं विलोपन है। आई.सी.एम.आर. का 'राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (NIRTH)' मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्थित स्थायी राष्ट्रीय संस्थान है, जिसे जनजाति समुदायों की विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अनुसंधान कार्य की योजना बनाने, उसके संचालन तथा समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। यह संस्थान इंडीजेनस पापुलेशंस के स्वास्थ्य के लिए 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) का सहयोगी केंद्र भी है।

जिस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उसके अनुसार 'राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (NIRTH)' मध्यप्रदेश सरकार एवं एफडीईसी–इंडिया मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों हेतु राष्ट्रीय एवं/अथवा डब्ल्यू. एच.ओ. के मापदंडों के अनुसार वैक्टर नियंत्रण (घरों के अंदर रेसीड्युअल स्प्रे और/या कीटनाशकों से उपचारित लंबे समय तक चलने वाली मच्छरदानियों –LLINs) के उपयोग द्वारा अथवा केस मैनेजमेंट (तुरंत ऑन द स्पॉट मलेरिया की जांच एवं त्वरित उपचार) द्वारा संयुक्त रूप से मंडला जिले से मलेरिया के उन्मूलन एवं उसके पुनः प्रारंभ की रोकथाम के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। एफडीईसी–इंडिया पर स्वतंत्र रूप से इस परियोजना को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व रहेगा, जिसमें NIRTH/ICMR, मध्यप्रदेश सरकार एवं सभी उपयुक्त स्टेकहोल्डर्स का सहयोग रहेगा। वे 3 से 5 वर्षों की समयावधि में मलेरिया उन्मूलन परियोजना को मंडला जिले के 1,233 ग्रामों को

शामिल करते हुए कार्यान्वित करेंगे। मंडला में मलेरिया मुक्त भारत डिमांस्ट्रेशन परियोजना के जनवरी, 2017 में लांच होने की संभावना है।

हस्ताक्षर किए गए करार पर 'सनफार्मा' के प्रबंध निदेशक श्री दिलीप सांघवी की टिप्पणी, ''सन फार्मा ने एक ऐसे लक्ष्य को लेकर एफडीईसी–इंडिया की स्थापना की है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए जाने वाले प्राथमिक कदमों से संबंधित है और जो रोगों के उन्मूलन व नियंत्रण की दृष्टि से उपयुक्त स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए प्रासंगिक हैं। 'पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप' करार, जिस पर आज हस्ताक्षर हुए हैं, भारत से 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 'सनफार्मा' सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई इस महत्वपूर्ण पहल का एक हिस्सा बनने पर सम्मानित और उत्साहित है, जिससे लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकेगा, बीमारियों की रोकथाम हो सकेगी और समुदायों की आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा, जिन पर मलेरिया का असर हुआ है।''

'फाउंडेशन फॉर डिजीस एलीमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया' (एफडीईसी–इंडिया) के अध्यक्ष डॉ. एस.वाई. कुरैशी के अनुसार, ''मैं खुश हूं कि 'एफडीईसी–इंडिया भारत में मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए पहला कदम उठा रही है। 'सन फार्मा' जिसने एफडीईसी–इंडिया' की सीापना की है, बधाई के पात्र हैं। मलेरिया उन्मूलन को संपूर्ण विश्व में प्राथमिकता दी गई है और उन्मूलन के लिए 2030 का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश सरकार और आईसीएमआर के साथ करार पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ हम मलेरिया उन्मूलन परियोजना का शुभारंभ कर रहे हैं। 'एफडीईसी–इंडिया', मध्यप्रदेश सरकार और आईसीएमआर के बीच 'पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप' स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें और भावी स्वास्थ्य संबंधी पहलों में अन्य संगठन 'एफडीईसी–इंडिया' के साथ मिलकर कार्य करेंगे।''

भारत सरकार, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की सचिव एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की महानिदेशक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार, '' मैं राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, सनफार्माज फाउंडेशन फॉर डिजीस एलीमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया और मध्यप्रदेश सरकार को मंडला में मलेरिया विलोपन परियोजना प्रारंभ करने के लिए बधाई देती हूं। वैक्टर नियंत्रण के फील्ड–परीक्षित एवं प्रमाणित साधनों के उपयोग एवं रैपिड डायग्नोसिस व त्वरित उपचार द्वारा केस मैनेजमेंट के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य मंडला जिले से मलेरिया का विलोपन करना है। सामुदायिक बैठकों, स्थानीय हाट–बाजारों, स्कूली बच्चों और महिलाओं इत्यादि के माध्यम से समुदाय की सघन सहभागिता इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक होगी। आईसीएमआर सक्रिय रूप से भागीदारी करेगा और पूर्ण लॉजिस्टिक एवं तकनीकी सहयोग व सहायता उपलब्ध कराएगा। इस डिमांस्ट्रेशन परियोजना से जो शिक्षाएं प्राप्त होंगी, वे मध्यप्रदेश और देश के बाकी भागों में मलेरिया विलोपन कार्यक्रम की योजना तैयार करने में उपयागी होंगी।''

मध्यप्रदेश सरकार, आयुक्ते, स्वास्थ्य डॉ. पल्लवी जैन गोविल के अनुसार, '' मलेरिया के कारण प्रभावित जन–समूहों, व्यक्तियों और समुदायों पर अत्यधिक आर्थिक एवं सामाजिक भार पड़ता है। देखते हुए कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, जिसकी पूर्णतः रोकथाम की जा सकती है, मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण एवं विलोपन के लिए और अधिक सघन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं को मंडला जिले से मलेरिया के विलोपन के लिए सहयोग करने हेतु उन्हें बधाई देती हूं। मंडला जनजाति बहुल आबादी वाला जिला है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में और दुर्गम भू–भाग में स्थित है। मंडला के आसपास कई नदियां हैं और यह क्षेत्र विपुल वन–संपदा से संपन्न है। इस जिले में मलेरिया एक स्थानिक रोग है। यह राज्य मंडला जिले में मलेरिया का विलोपन करने की ओर अग्रसर है, इसके लिए प्रारंभिक अवस्था में ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एवं मलेरिया के पूरे इलाज के रूप में इंटरवेंशन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसके साथ–साथ API 5 या उससे अधिक वाले सब–सेंटर्स में कीटनाशकों से उपचारित लंबे समय तक चलने वाली मच्छरदानियों –LLINs की आपूर्ति एवं 1 से 4.9 वाले क्षेत्रों में छिड़काव अभियान जैसे प्रभावी वैक्टर नियंत्रण उपायों द्वारा मलेरिया के विलोपन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वैक्टर संबधी अध्ययन

एवं मलेरिया के जानपदिकरोग–वैज्ञानिक मूल्यांकन के रूप में तकनीकी सहयोग तथा सर्वेलेन्स ऑपरेशन, सूचना शिक्षा एवं संचार, व्यवहार परिवर्तन संवाद, वैक्टर नियंत्रण के साथ ही मलेरियारोधकों की आपूर्ति के रूप में एफडीईसी–इंडिया द्वारा दिए जा रहे अतिरिक्त सहयोग से राज्य को मंडला जिले से मलेरिया का विलोपन करने में मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करती हूं कि सभी तीनों सहभागियों के सघन साझा प्रयासों से मंडला जिले से मलेरिया का विलोपन होगा और यह एक ऐसा मॉडल होगा, जिसकी प्रतिकृति इस राज्य के अन्य जिलों तथा देश के अन्य भागों में की जा सकती है।

आज जिस करार पर हस्ताक्षर किए गए है, वह निम्नांकित की भी अनुमति प्रदान करता है :–

1. आईसीएमआर, मध्यप्रदेश अथवा भारत में किसी अन्य राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय को अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों अथवा राष्ट्रीय महत्व की किसी बीमारी या अन्य संक्रामक या क्रोनिक बीमारियों के उन्मूलन/विलोपन से संबंधित कार्य करने के लिए 'एफडीईसी–इंडिया' के साथ टाई–अप करना।
2. किसी अन्य सरकारी, अर्द्ध–सरकारी संगठन या संस्थानों को मलेरिया मुक्त भारत (मंडला) परियोजना में शामिल होना अथवा संचारी रोगों, क्रोनिक रोगों के उन्मूलन के लिए इसी प्रकार की परियोजनाएं विकसित करने अथवा किन्हीं अन्य समान उद्देश्यों के लिए 'एफडीईसी–इंडिया' के साथ करार करना।
3. किसी अन्य पब्लिक या प्राइवेट एनटिटी, स्टेकहोल्डर अथवा संगठन को मलेरिया मुक्त भारत (मंडला) परियोजना में प्रतिभागिता करने एवं इस परियोजना के लिए अपने योगदान संबंधी प्रयासों, संसाधनों या आर्थिक मदद उपलब्ध कराकर 'पीपीपी' के लिए एक पार्टी होना।

भारत सरकार ने मलेरिया के संबंध में, नवंबर, 2015 में 'एशिया पेसिफिक लीडर्स मलेरिया एलाइंस (जिसे इसके बाद ''एपीएलएमए'' के रूप में लिखा जाएगा) रोडमैप के समर्थन के बारे में क्षेत्र का मार्गदर्शन करने में मदद कर सशक्त क्षेत्रीय नेतृत्व दिखाया है। केवल तीन माह के अंदर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ''द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलीमिनेशन इन इंडिया'' का प्रारंभ कर दिया था और भारत में मलेरिया विलोपन का लक्ष्य 2030 के रूप में निर्धारित किया था। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के अनुमानों के अनुसार दक्षिण–पूर्व एशिययाई क्षेत्र के देशों में से भारत में लगभग 70% मलेरिया के केस पाए जाते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर भारत में सर्वाधिक मौतों की संख्या पाई जाती है, जिसमें अनुमानित रूप से 181.3 मिलियन उच्च जोखिम वाले तथा 997.4 मिलियन लोगों को निम्न एवं उच्च जोखिम है। मलेरिया विकास, बचत एवं निवेश, वर्कर उत्पादकता एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में बाधा बनते देखा गया है। मलेरिया के कारण स्कूल और कार्यस्थलों पर अनुपस्थिति भी बढ़ती देखी गई है।यह देखा गया है कि मलेरिया और गरीबी में सह–संबंध है और जिन देशों में मलेरिया स्थानिक बीमारी के रूप में है, उनमें आर्थिक विकास की दरें धीमी होती हैं।

'सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड' के बारे में (CIN – L 24230GJ1993PLC019050)

'सन फार्मा' विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी स्पेशियल्टि जेनेरिक फार्मास्युटिकल कंपनी और भारत की सबसे फार्मास्युटिकल कंपनी शीर्षस्थ है। सतत आगे बढ़ते बिजनेस, विकसित होती अर्थव्यवस्था और एक अत्यंत कुशल टीम के सहयोग से हम समयबद्ध तरीके से उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मुहैया कराने में सक्षम हैं। यह कंपनी ऐसी दवाएं उपलब्ध कराती है, जो उच्च–गुणवत्ता वाली हैं और जिन्हें आम आदमी खरीद सके तथा जिन पर विश्व के 150 से अधिक देशों के ग्राहक और रोगी विश्वास करते हैं। 'सन फार्मा' ने पूरे विश्व में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जिसे 6 देशों में फैली 47 उत्पादन इकाइयों, पूरे विश्व में फैले अनुसंधान व विकास केंद्रों तथा 50 से अधिक देशों के काम करने वाले लोगों से मदद मिलती है। मार्च, 2016 को समाप्त 12 माह का समेकित राजस्व अनुमानतः 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें यू.एस. का योगदान 2.1 बिलियन है। भारत में कंपनी चिकित्सकों के 12 विभिन्न वर्गों में अग्रगण्य है, भारत के शीर्ष के 300 ब्रांड्स में से इसके 32 ब्रांड्स हैं। कंपनी ने

आज के उभरते 100 से अधिक बाजारों में और 6 बाजार पश्चिमी यूरोप में अपने पदचिह्न अंकित किए हैं। इसका ग्लोबल कंज्यूमर हैल्थकेयर बिजनेस 4 ग्लोबल बाजारों में शीर्ष की 10 कंपनियों में है। इसके एपीआई बिजनेस फुटप्रिंट्स को विश्व भर में फैली 14 विश्वस्तरीय उत्पादक इकाइयां सुदृढ़ बनाती हैं। 'सन फार्मा' इनोवेशन के माध्यम से उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करती है, जिसका आधार इसके सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं हैं, जिनमें लगभग 2000 वैज्ञानिक कार्य करते हैं और वार्षिक राजस्व का 8% से अधिक अनुसंधान एवं विकास में निवेश है।

'फाउंडेशन फॉर डिजीस एलीमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया' के बारे में (CIN:U85190MH2016NPL286097)

'सन फार्मा' द्वारा अपने कार्पोरेट सोशल रिसपांसिबिलिटी इनीशिएटिव के तौर पर 'एफडीईसी–इंडिया' की स्थापना की गई है। यह एक 'नॉट–फॉर–प्रॉफिट' कंपनी है, जो कंपनी एक्ट, 2013 के सेक्शन–80 के तहत सन हाउस, प्लॉट नं. 201बी/1, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063 स्थित इसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर रजिस्टर्ड है। यह फाउंडेशन बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा शासित होता है (डॉ. एस.वाई. कुरैशी, अध्यक्ष, डॉ. के.के. अग्रवाल एवं श्री अजदार खान) तथा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों (डॉ. अलताफ लाल, श्री अनिल राघवन, डॉ. श्रीनाथ रेड्डी, डॉ. पी.एल. जोशी, डॉ. नीलिमा क्षीरसागर, डॉ. जेकब जॉन) द्वारा इसे सहयोग प्रदान किया जाता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के बारे में

'भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) जैवआयुर्विज्ञान अनुसंधान की योजना बनाने, समन्वय एवं संवर्धन करने का सर्वोच्च निकाय है, यह आयुर्विज्ञान अनुसंधान कार्य से संबद्ध विश्व के प्राचीनतम निकायों में से एक है। भारत सरकार ने देश में आयुर्विज्ञान अनुसंधान के कार्य को प्रायोजित करने व समन्वय करने के विनिर्दिष्ट उद्देश्य को लेकर 'इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन' (IRFA) की स्थापना की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इस संगठन में और IRFA के कार्यकलापों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। 1949 में इसे नया नाम 'इंडियन काउंसिल ऑफ मेडीकल रिसर्च (ICMR) दिया गया और इसके कार्यों का काफी विस्तार किया गया। आई.सी.एम. आर. का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। परिषद की अनुसंधान संबंधी प्राथमिकताएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के सदृश हैं, जैसे संचारी रोगों का नियंत्रण एवं प्रबंधन, प्रजनन नियंत्रण, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, पोषण संबंधी विकारों का नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवा प्रदाय हेतु वैकल्पिक कार्यनीतियां विकसित करना, पर्यावरणीय एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं का संरक्षा सीमाओं के अंदर समाधान; प्रमुख गैर–संचारी रोगों, जैसे कैन्सर, कार्डियोवेस्कुलर रोगों, अंधापन, डायबिटीज और अन्य मेटाबोलिक एवं हीमेटोलॉजिकल रोगों पर अनुसंधान; मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान एवं औषध अनुसंधान (पारंपरिक रोगोपचारों सहित)। ये सभी प्रयास कुल रोग–भार में कमी लाने तथा लोगों के स्वास्थ्य व सेहत को बेहतर बनाने को दृष्टिगत रखते हुए किए जाते हैं। परिषद की 'गवर्निंग बॉडी' की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की जाती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों में 'साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड' द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें विभिन्न जैव–आयुर्विज्ञान विषयों के अग्रगण्य विशेषज्ञ होते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए कृपया सन फार्मा कार्पोरेट कम्युनिकेशन्स से संपर्क करें

Frederick Castro + 91 9920665176, frederick.castro@sunpharma.com

इन्वेस्टर रिलेशन्स संपर्क

Nimish Desai +91 9820330182 nimish.desai@sunpharma.com